Agricultural Refinance Corporation

2507. Shri Maniyangadan: Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 798 on the 8th April, 1965 and state:

(a) whether a scheme for financing new rubber plantation from the Agricultural Refinance Corporation was submitted by the Rubber Board;

(b) whether there was any discussion on the matter between the representatives of the Rubber Board and the Reserve Bank of India; and

(c) if so, the decision taken in the matter?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): (a) and (b). A scheme was formulated by the Rubber Board in September 1964 and was submitted to the Agricultural Refinance Corporation. The question of financing the plantation or replantation of rubber has also been independently under consideration and the Corporation has examined this proposal in consultation with the Rubber Board.

(c) The Rubber Board has indicated that facilities for the technical scrutiny and appraisal of various schemes will be provided by it free of cost. Applications received from individual borrowers will now be considered on their merits.

12.03 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

FIRING BY PAKISTANI FORCES ON INDIAN POLICE POST EAST OF KANJARKOT

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): I call the attention of the Minister of Defence to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon:

The reported firing by Pakistani forces on an Indian Police post about 50 miles East of Kanjarkot on the 20th April, 1965.

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): Mr. Speaker, Sir. Since the Army has taken over the Sind-Kutch border it has been patrolling vigorously and in strength upto our border. These patrols have been doing useful work and wherever they have met opposition they have taken effective action. For reasons that Members will fully understand, we have not been publicising where and how these patrols have been working.

On the night of 19th and 20th April, 1965 one of these patrols clashed with a large Pakistani Force on the Pakistani border.

Recently Pakistani tactics have been to shell from their own side of the borders on posts held on our side of the border. This shelling was to be expected and they have not made any difference to the location of the posts we are holding or the arrangements we have in mind. Shelling is not confined to the Pakistani side only—I can assure Members that we also use our guns to a very good effect.

Shri Narendra Singh Mahida: During the regime of the former State of Kutch, the boundary between the then Kutch State and Sind were very clearly marked. There were customs roads and small boundary marks on those territories. Kanjarkot is positively in the Indian territory and it is now occupied by Pakistani forces. What prevents our Government to vacate this Pakistani invasion on our own territory....

Mr. Speaker: That answer has been given. It need not be repeated.

Shri Narendra Singh Mahida: Then, may I ask the Defence Minister what is the total area of the Rann of Kutch claimed by Pakistan so far?

An hon. Member: No, no.

Mr. Speaker: Why should that be asked?

Shri P. Venkatasubbaiah (Adoni): While congratulating the Defence Minister for the bold statement he has made to repel the Pakistani aggression, may I know from the hon. Defence Minister whether he will see that the entire border area is entrusted to the military rather than to the police force as we are just now hearing the news that on the Rajasthan border there is intensive military action by Pakistan and, if so, what action the Defence Minister is going to take in that direction to constitute a border military force as early as possible?

Shri Y. B. Chavan: As far as the Kutch border is concerned, the operational command is with the Army.

May I make a request to you and through you to the Members of this House that as we are dealing with the situation from day to day and from hour to hour, it will not be in the interest of our own security that I should be asked about matters of detail and matters of fact?

Mr. Speaker: I think that that would be better. Members should also realise it. It should be the responsibility of the Members also. They should also be as mindful of the interests of the country as anybody else.

Shri N. Dandeker (Gonda): If that will help, may I support the request of the Defence Minister?

Mr. Speaker: The hon. Member should face the Members on his side and say this.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): We would request the Opposition also not to ask any questions on this.

Shri Narendra Singh Mahida: If the leader of the House forwards this suggestion or requests us, we sholl not ask any questions.

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): What is this? Details are not being asked at all.

Mr. Speaker: But in the question that had been put, details had been asked.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : अगर हमें यह विश्वास हो कि पिछले दिनों जो आक्रमण हुआ है उस के बाद गवर्नमेंट ने कोई कार्यवाही की है तो बात दूसरी है । हमें केवल आश्वासन दिया गया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया । आये दिन वह हम पर आक्रमण कर रहा है, तब हम कैसे इस बात पर विश्वास कर लें सरकार का और कोई सवाल न पूछें ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, विश्वास नहीं करते तो मत कीजिये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं प्रधान मंत्री से बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछली बार यह विश्वास दिलाया था सदन के अन्दर कि जब तक कंजरकोट का इलाका पाकिस्तान खाली नहीं करता तब तक हम बात नहीं करेंगे । हम ने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उस के बावजूद भी उस ने हम पर आक्रमण किया । तो क्या सरकार उन से बात करने के लिये तैयार है जब तक वह आक्रमण को खत्म नहीं करता । हमारी सीमा जितनी है उस पर आज खतरा आ गया है ।

Shri Raghunath Singh: That is not relevant at all.

अध्यक्ष महोदय : बहुत दफे दरख्वास्त की गई है कि हर एक सप्लिमेन्टरी में यह खयाल रक्खा जाये कि हमारा कोई इंटरेस्ट उस से सर्व होता है या नहीं । इस बात के लिये हम सब को खयाल रखना चाहिये ।

The Members in the Opposition as also the Members on the Government Benches should be equally interested. अगर हम किसी वक्त गवर्नमेंट की गलती भी समझें, तो भी कंट्री का इंटरेस्ट गवर्नमेंट से ज्यादा ऊंचा है । उस का खयाल तो जरूर

[अध्यक्ष महोदय]

ही होना चाहिये। चूंकि कोई मैम्बर गवर्नमेंट में कोई कमी समझता है इसलिये सोचे कि सवाल जरूर कर दिये जायें तो इस से कंट्री का इंटरेस्ट सफर करता है। हम और किसी बात की परवाह करें या न करें लेकिन इस बात का खयाल हमें जरूर रखना चाहिये। यह मैं सब मेम्बरों से कहूंगा।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप ने जो कुछ कहा है मैं उस का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन हम विरोधियों को जिस ढंग से विश्वास में लिया जाना चाहिये उस ढंग से नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप विरोधी हैं तो गवर्नमेंट के हैं, मुल्क के तो नहीं हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : कल ही इस सदन में यह घटना हुई कि हमारे एक माननीय सदस्य को सात रोज के लिये सदन से निकाला गया।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह आप पर छोड़ता हूं।

Shri Narendra Singh Mahida: May I suggest that Government should come out with a comprehensive statement on Kutch from time to time.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं आप की मानने के लिये तैयार हूं।

श्री मधु विमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है : मुल्क के हित और सत्तारूढ़ दल के हित में आप ने फर्क किया। लेकिन सत्तारूढ़ दल के हाथ में इस वक्त मुल्क की बागडोर है और मुल्क के हित को वह चौपट कर रहे हैं। कंजरकोट का किला पाकिस्तान के हाथ में चला गया, उस को वापस लेने के लिये कोई बात नहीं हो रही है। इसलिये मैं आप से जानना चाहता हूं कि जो फर्क आप कर रहे हैं उस से सत्तारूढ़ दल के गलत कामों को बचाने का काम क्या नहीं हो जाता है। इस लिये जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन का सीधा जवाब देने के लिये आप को गवर्नमेंट से कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये। मुझे जो कहना था वह मैं ने कह दिया।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं कहना चाहता था कि कल जब इस हाउस में सवाल पूछा गया सीमा पर जो आक्रमण हो रहा है उस के सम्बन्ध में तो एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य से कहा कि वह गैलरीज को सुनाना चाहते हैं। मेरा आप से यह निवेदन है कि हम जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो आप से यह आशा करते हैं कि आप सरकार से जवाब दिलवायेंगे। लेकिन जब यहां से हमारे मेम्बरों को निकाला जाता है तो हम कैसे करें।

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल करें। अब मेम्बर को निकालने का सवाल नहीं है यहां पर।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस समय उस इलाके में पाकिस्तान ने किस प्रकार की तैयारी की हुई है, उस ने कितने सैनिक जमा किए हुए हैं और कौन कौन से हथियार वहां ला कर रखे हैं और क्या हम उन को बिना बात चीत के लड़ाई का जवाब लड़ाई से दे कर वहां से हटा सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मिनिस्टर साहब इस का जवाब देना चाहते हैं।

Shri Y. B. Chavan: No, Sir.

श्री हुकन चन्द कछवाय : आप ऐसा कह के तो मंत्री महोदय को मना करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी इस सवाल की इजाजत नहीं देता।

श्री यशपाल सिंह (कराना) : मुझे श्री चह्वाण के वक्तव्य पर भरोसा है, और मुझे विश्वास है कि वह देश की आन के लिए सब कुछ करेंगे । लेकिन क्या यह जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपनी सड़कों का निर्माण कर लिया है और वह बड़ी आसानी से गोलाबारी कर सकता है, उसी तरह हम भी अपनी सड़कों का निर्माण करें । यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

Shri Y. B. Chavan: The question of having communications is certainly actively taken up. Naturally they have got their firm land immediately after the Rann of Kutch ends. They have certainly some advantage about it. But as I said, we have also actively taken up this matter.

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, सन् 1947 के बाद से देश की सरहदों पर, चाहे वे पाकिस्तान के नजदीक थीं या चीन के नजदीक थीं, विदेशियों ने समय समय पर कब्जा किया है और भारत ने ऐसे किसी इलाके में जवाबी कार्यवाई नहीं की है । इस का परिणाम यह हो रहा है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा चीन और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी सरहद इतनी लम्बी चौड़ी है कि हम इस का बचाव फौजी दीवार खड़ी कर के नहीं कर सकते । उस के लिए हम को .....

अध्यक्ष महोदय : आप को जो कहना था वह तो कह चुके, अब सवाल पूछिये ।

श्री बागड़ी : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हमारी कितनी जमीन चीन और पाकिस्तान ने इस तरीके से बार बार हमले कर के अपने कब्जे में कर ली है, और क्या उस को छुड़ाने के लिये हमारी सरकार यह नीति अपनाएगी कि जिस तरीके से वे वहां हमारी कमजोरी देखते हैं उस इलाके पर हमला कर देते हैं, इसी तरीके से हम भी जहां उन की कमजोरी देखें उन के उस इलाके पर हमला कर दें और उसे अपने कब्जे में कर लें ?

अध्यक्ष महोदय : चीन के सवाल की तो मैं इजाजत नहीं देता । पाकिस्तान के पास बारडर में हमारा कितना इलाका है यह मिनिस्टर साहब बतला सकते हैं तो बतला दें ।

Shri Y. B. Chavan: Actually, as the Home Minister and the Prime Minister have explained in their statements here, on this border they have two standing posts. If at all one can speak of occupation, I can only say that these two posts are under their occupation. But I cannot concede the position that they have occupied any large area as such. As I mentioned in my statement, even in those areas we are effectively patrolling our border. So it is not a question of merely conceding how many miles they occupied.

About the vacation of Kanjarkot, I think the Prime Minister has explained our attitude in this particular matter more than once on the floor of the House.

श्री बागड़ी : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया । एक सवाल तो नीति का है । मैं ने कहा था कि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा उन के कब्जे में है, और जिस तरीके से हमारी गफलत और कमजोरी के आधार पर वे हमारे मुल्क की सीमा पर कब्जा कर लेते हैं उसी तरीके से हम भी – क्योंकि हम सारी सीमा पर फौज खड़ी कर के अपनी सीमा को नहीं बचा सकते—जहां उन की कमजोरी देखें वहां उन की जमीन पर कब्जा कर लें क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो वे हमारी जमीन वापस करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यह सजेशन है । यह उन का सोचना है, इस का जवाब क्या हो सकता है ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : मैं यह जानना चाहता हूं कि कंजरकोट में

[श्री विश्राम प्रसाद]

कितनी भूमि पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है और कितनी चौकियां बना ली हैं, और भारत सरकार इसको बार्डर डिस्प्यूट कहती है, एग्रेशन कहती है या इनवेजन कहती है ?

अध्यक्ष महोदय : प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये सब बातें कह दी हैं। इन के बारे में वे स्टेटमेंट दे चुके हैं।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : कंजरकोट के प्रश्न पर इसी सदन में प्रधान मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा था कि वे पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में वार्ता अवश्य करेंगे, लेकिन उस वार्ता में यह शर्त होगी कि कंजरकोट को पाकिस्तान खाली कर दे। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने यह साफ साफ कह दिया है कि वह कंजरकोट खाली नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या कार्यवाई करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह यह बतलायेंगे कि वह क्या कार्यवाई करने जा रहे हैं ? यह आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या वह बतलायेंगे कि वह क्या कार्यवाई करने जा रहे रहे हैं ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : कुछ भी करने को तैयार हैं या नहीं।

श्री रामसेवक यादव : क्या कार्यवाई करना चाहते हैं, यह मैं नहीं जानना चाहता। उनकी नीति क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अभी कई जवाब आखिरी तौर पर पाकिस्तान से नहीं आया है, जब आज आगा तो हम निर्णय लेंगे।

श्री रामसेवक यादव : अखबारों से पता चलता है कि हिन्दुस्तान में जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी सरकार का जवाब बता दिया है। क्या उसके अलावा भी कोई उत्तर आने को है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने कहा कि हम इन्तिजार कर रहे हैं।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का सवाल है।

इस कंजरकोट की समस्या को हम खुद उलझा रहे हैं।

Shri Raghunath Singh: Under what rule?

श्री बागड़ी : अन्दर कुछ है और बाहर कुछ है, एक क्षण में कुछ है, दूसरे क्षण में कुछ है। मैं प्रधान मंत्री से आप की मार्फत निवेदन करूंगा कि वह स्थिति के बारे में एक स्पष्ट ब्यान दें। उसके बारे में जो बार बार झिक झिक होती है इससे देश का अहित होता है।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए मैं कौन से रूल के मातहत फैसला दूं ?

श्री बागड़ी : फैसला तो ऐसे ही रूल्स में हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : और आप इसी तरह से प्वाइंट आफ आर्डर रेज करते रहेंगे। बड़े अफसोस की बात है कि जब मैं पूछता हूं क्या फैसला दूं तो वह उसको मजाक में टालने की कोशिश करते हैं और कहा हैं कि ऐसे ही होता रहता है।

श्री बागड़ी : आप प्रधान मंत्री को कहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा फर्ज नहीं है।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : श्री बागड़ी की बात दुरुस्त है। ऐसी ही खबर आयी है, और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार

की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है । यह खबर है कि हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव ने भारत में पाक हाई कमिश्नर को आश्वासन दिया है कि कंजरकोट खाली करने वाली शर्त सिर्फ बातचीत के लिए नहीं शस्त्र सन्धि के लिए भी लागू नहीं होगी । यानी कंजरकोट खाली करना शस्त्र सन्धि के लिए भी जरूरी नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे सचिव ने सचमुच ऐसा कहा है, और अगर कहा है तो उसके बाद प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इतने ब्योरे में जाना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन जो .

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि किसी मंत्री ने ऐसा कहा है . . . .

श्री किशन पटनायक : मंत्री ने नहीं, सेक्रेटरी श्री सी० एस० झा ने कहा है ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ऐसा कोई बयान तो उन्हों ने नहीं दिया है ।

श्री किशन पटनायक : आश्वासन दिया है भारत में पाक हाई कमिश्नर को ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पाकिस्तान ने दो तीन बातें लिखी थीं, उन बातों को हम ने मान कर बात करने के लिए कहा । उन में एक सीज फायर है, दूसरी बात है स्टेटस क्वो रखने की, और अगर उस में बात तै हो जाए तो फिर हमारी बाउन्डरी क्या हो इस के बारे में हाई लेविल पर विचार हो । ये प्वाइंट उन की तरफ से आए, जिनको हमने स्वीकार किया है, और अब उसके बाद अगर उनका जवाब आवेगा कि हम इसके लिये तैयार हैं, तो हम आगे सोचेंगे ।

श्री किशन पटनायक : बात साफ नहीं होती है इसलिये बार बार प्रश्न दुहराना पड़ता है ।

अध्यक्ष महोदय : बार बार प्रश्न करने की जरूरत नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, स्टेटस क्यो से क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : एक एक चीज पर मैं नहीं जा सकता । (इंटरप्शंस) आर्डर, आर्डर । आप ने सवाल किया जवाब उस का आया ।

श्री किशन पटनायक : जवाब कहां आया ? मेरे सवाल का मतलब यह निकलता है कि शस्त्र संधि के पहले कंजरकोट खाली करना चाहते हैं यह सरकार की नीति है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : गवर्नमेंट की क्या पालिसी है वह उन्हों ने बतला दी है । उन्हों ने जवाब दे दिया है ।

श्री किशन पटनायक : जवाब नहीं दिया ।

Shrimati Renu Chakravartty: There is some difference between status quo and status quo ante. If it is status quo, Kanjarkot remains with Pakistan.

Shri Lal Bahadur Shastri: I mean status quo ante.

श्री मधु लिमये : स्टेटस क्यो को युद्धपूर्व स्थिति कहा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने साफ कह दिया कि हम स्टेटस क्यो ऐंटी चाहते हैं अब इस से ज्यादा और आप क्या चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय का जवाब सुन कर यह मालूम होता है कि कच्छ औफ रन में पाकिस्तान के किसी भी हमले का मुकाबला करने की हमारी पूरी तरह से तैयारी है लेकिन आज अखबार में निकली इस खबर की ओर भी क्या उन का ध्यान गया है :—

"Pakistan build up on Rajasthan border."

इस से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान सिर्फ कच्छ के इलाके में ही नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा न कर के गोपनीय तरीके से

[श्री स० मो० बनर्जी]

युद्ध की तैयारी कर रहा है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह तसल्लीबख्श जवाब है जो उन्होंने कच्छ के बारे में दिया है और क्या यह सदन दूसरे अपने सीमान्त प्रदेशों के बारे में भी यह समझ ले कि उन की रक्षा करने के लिये भी भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी हां ।

Shrimati Renu Chakravartty: In view of the fact that the border is now becoming alive even fifty miles further east of Kanjarkot and it may blow up in any other area, may I know whether Government is conceding the demands made by various States for co-ordinated defence of the entire border with Pakistan, both east and west?

Shri Y. B. Chavan: I think I have answered this question in the affirmative.

Shri Daji (Indore): Is it a fact that from documents and papers captured from Pakistani soldiers it has come to our knowledge that these activities were preplanned and prepared by them from early March and that they are not the result of any spontaneous action?

Shri Y. B. Chavan: I refuse to discuss those documents here. (*Interruptions*).

Shri Daji: No, no. He should say whether it is disclosed from those documents that Pakistan has done this deliberately and in a prepared manner?

Shrri Y. B. Chavan: Yes, Sir. I thought the question was to disclose the duration that they took, the time they took.

Shri Raghunath Singh: Is it a fact that Pakistan is employing well-trained and fully equipped regular Armed Forces on the border?

Shri Y. B. Chavan: Yes, Sir.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): When I was in West Pakistan during the 2nd week of April, I saw a long statement by the Foreign Minister of Pakistan Mr. Bhutto urging among other things that on grounds of historical pre-emption and the legal precept Pakistan is entitled to an area of 3500 sq. miles east of Kanjarkot. I would like to know whether there is any element of plausibility in this tall claim?

Shri Y. B. Chavan: No, Sir.

Shri Kapur Singh: It is a long statement; it must have come to their notice.

Mr. Speaker: He says: no.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं यह जानना चाहूंगा कि कश्मीर को राष्ट्र-संघ में गये हुए 17 साल हो गये, लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा गये हुए 3 साल हो गये और अब यह कच्छ में कंजरकोट चला गया है तो इस के लिए क्या हम ने कोई ऐसा टाइम लिमिट तय की है कि अगर इतने समय तक उस का जवाब नहीं आयेगा या वह वहां से पीछे नहीं हटेंगे तो हम उस मुद्दत के बीत जाने के बाद कार्यवाही करेंगे या फिर इस को भी राष्ट्र-संघ में ले जायेंगे ?

Shri Y. B. Chavan: Time-tables cannot be discussed here.

श्री हुकम चन्द कछवाय : सैनिक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री रघुनाथ सिंह : राष्ट्र-संघ से इस से क्या मतलब है ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : इसे राष्ट्र संघ में ले जाया जायगा या नहीं ? आखिर उन का हम कब तक इंतजार करेंगे ?

Shri Himatsinhji (Kutch): The whole question has been put in a mess. First of all, Gujarat Government is responsible for this border and they have failed to look after this border and protect it. Now, afterwards, so many statements have been made and no clear-cut policy is coming forth. The Prime Minister made a statement and he has made a speech outside.

Mr. Speaker: Now, he may put his question.

Shri Himmatsinhji: I come from that area, Sir; I feel very strongly about an area for which my ancestors fought and paid with blood and life. You should realise it. I will not ask any questions on defence matters, but. . .

Mr. Speaker: Peter Alvares.

Shri Himmatsinhji: ....I would like to know one thing.

Mr. Speaker: He said that he did not want to put any question.

Shri Himmatsinhji: Not on defence. It is reported in some papers and by some persons also that Pakistan has occupied one area where they have brought in some water and water facilities and they also call it Shakur. Is this a fact and if so will the Minister give any details about it?

Shri Y. B. Chavan: About what preparations they are making and other things, it will not be right for me to discuss our assessments of their preparations.

Shri Alvares (Panjim): The intrusion by Pakistan is like a hydra-headed monster. You try to meet it at one place and it manifests itself in another. This morning there were newspaper reports about their activities not merely in the Kanjarkot area but also in Rajasthan border, in Jammu and in Berubari. It is exasperating as well as demoralising. In view of this fact may I ask the Prime Minister whether he will insist, before negotiations, that there should be complete cease fire all along the Indo-Pakistan border?

Mr. Speaker: I cannot compel which Minister should reply.

Shri Alvares: He is about to reply, Sir.

Shri Lal Bahadur Shastri: Why should it be exasperating and demoralising? After all they might make their preparations but we are also prepared to meet them as and when the circumstances arise.

Shri Alvares: They are the aggressors; Pakistan is the aggressor. We cannot meet them at those places. That is exasperating.

श्री बागड़ी : तैयारी होगी ? खाक तैयारी कीजियेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस तरह से कहने से क्या बनेगा ? क्रिटिसिज्म बेशक की जाय लेकिन महज इस तरह से कहने से भी तो तैयारी नहीं हो जाती है जैसे कि यहां कहा जा रहा है ।

श्री बागड़ी : हम क्या करें ? जी जल रहा है उस का गुब्बार निकाल रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : क्या तैयारी होगी ?

श्री विश्वनाथ पांडेय (सलेमपुर) : रक्षा मंत्री ने अपने सीमान्त क्षेत्रों की रक्षा करने का जो आश्वासन दिया है उस के लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने इंडियन पुलिस पोस्टस पर जो गोलाबारी की है उस से इंडियन पुलिस पोस्टस का कितना नुकसान हुआ है और उस का कुछ अंश क्या पाकिस्तान की फोर्सेज के कब्जे में आ गया है ?

Shri Y. B. Chavan: I think information on this point was given on the floor of the House that they had attacked the Sardar post. It is not in their occupation really speaking. Immediately our regular armed forces

[Shri Y. B. Chavan]

have occupied this post and there were certainly casualties; there were heavy casualties on the Pakistan side.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य से अभी ऐसा प्रतीत हुआ कि जो तीन शर्तें पाकिस्तान की ओर से आई हैं बातचीत करने के लिए उन शर्तों को स्वीकार कर लिया जायगा और उस आधार पर बातचीत आरम्भ हो जायगी। कंजरकोट कच्छ में स्थित उन स्थानों के लिये जहां पाकिस्तान का आज अधिकार है तो क्या भारत सरकार पाकिस्तान से कंजरकोट और दूसरे इलाकों के सम्बन्ध में बातचीत का रास्ता खोल कर शत्रु को यह मौका नहीं दे रही है कि पहले वह आक्रमण कर के हमारे घर में कब्जा कर ले और फिर उस के बाद आक्रमण बंद कर के बातचीत की जाय ? इस तरीके से अपने क्षेत्रों को दूसरे के हाथों में दे दिया जाय, सरकार अपनी इस दुर्बल नीति को कब तक जारी रखना चाहती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री: मैं इस को कोई दुर्बल नीति नहीं समझता। अगर उन की तरफ से बातचीत करने का ऑफर किया जाय और वह ठीक बातें हों तो बातचीत के लिए हमारा राजी हो जाना मैं नहीं समझता कि हमारी दुर्बलता की नीति है। उस हालत में बातचीत करने से इंकार करना कोई एक बड़ी ताकत की निशानी नहीं है। जो बात सही है, आपसी बातचीत में हम अपने पक्ष को मजबूती से रक्खें और अगर बातचीत से हम लोगों में बात तय हो जाती है तो वह ठीक ही है लेकिन अगर तय नहीं होगी तो हम फिर उस पर विचार करेंगे कि आगे क्या किया जाय ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : कब्जा छोड़ कर ?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I am very happy to hear that this border has been put under the charge of our military. What I want to know is how the Pakistani forces have acquired so much mobility and efficiency that they have been able to shell an Indian post about fifty miles east of Kanjarkot. And, may I know if all that mobility and all that efficiency is due to the fact that they have been getting arms from America?

Shri Y. B. Chavan: Naturally, Sir, they have certain advantages. About mobility, as I explained, immediately beyond the Rann of Kutch they have got their farm land and, certainly, there are developed communications there and, therefore, they are taking advantage of that to frighten us with shelling, but they are very effectively replied to.

About those arms etc., we have made a statement on the floor of the House that at least in the first attack they had made use of certain American equipment.

12.31 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

PUBLIC NOTICE ON IMPORT POLICY FOR NEWSPRINT

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of the Public Notice No. 28-ITC(PN)|65, dated the 21st April, 1965, on import Policy for Newsprint for the year April, 1965—March, 1966. (Placed in Library. See No. LT-4233|65).

Emergency Risks (Coods) Insurance (Amendment) Scheme and Emergency Risks (Factories) Insurance (Amendment) Scheme.

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications:—

(i) The Emergency Risks (Goods) Insurance (Amendment) Scheme, 1965, published in Notification No. S.O| 923 dated the 27th March, 1965,